Technical Documentation Directorate
Bhagirath(English)& Publicity Section
****

725(A), North,Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi – 66.

Dated 2.2.2017

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings have also been uploaded on the CWC website.

S.Mahadkar 2.2.17
Assistant Director (publicity)

Encl: As stated above.

Editor, Bhagirath (English) & Publicity

Director (T.D.)

For information of Chairman &Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

Farm sector gets more, crop insurance raised

Jaitley promises access to increased credit and funds for irrigation

SPECIAL CORRESPONDENT

NEW DELHI: While farmers were disproportionately hit by demonetisation, Finance Minister Arun Jaitley focussed his promises on helping them access increased credit and said the government would channel more money for irrigation.

Budget documents suggest that allocations made to the Agriculture Ministry were ₹51,026 crore or about 6% over last year's updated estimates. "It [Budget Speech] is quite insipid," said Ajay Vir Jhakkar, Chairman, Bharat Krishak Samaj, as "there is no relief or measures to ease the effects of demonetisation."

On the back of a reasonable monsoon, agriculture is forecast to grow at 4.1% in the current year and Mr. Jaitley said the government would be focussed on keeping last year's promise to double farmer income in five years.

"We have to take more steps and enable the farmers to increase their production and productivity; and to deal with post-harvest challenges."

The target for agricultural credit in 2017-18 was fixed at ₹10 lakh crore, a "record" according to Mr. Jaitley.

The Fasal Bima Yojana (FBY), or the Prime Minister's farm insurance scheme, which covered 30% of cropped area in 2016-17 has been extended to 40% in 2017-18 and is expected to cover half the country in 2018-19.

The Budget provided ₹5,500 crore for the scheme last February but increased it to ₹13,240 crore to settle the arrear claims; ₹9,000 crore has been allotted for the scheme this year.

Farmer groups allege that more than them, insurance companies have benefited from the FBY scheme. "Expenditure on premium increased to ₹13,240 crore but covered only 26.5% of farmers. All this money went to insurance companies. There is no mention of how much claims the farmers got in return," farmer group, Swaraj Abhiyaan said in a statement.

A dedicated irrigation fund set up last year by NABARD to improve the coverage and efficiency of irrigation services would double its corpus from ₹20,000 crore to ₹40,000 crore. The National Agricultural Market (e-NAM) will be expanded from the current 250 markets to 585 APMCs and a Dairy Processing and Infrastructure Development Fund set up in NABARD with a corpus of ₹8,000 crore over 3 years.

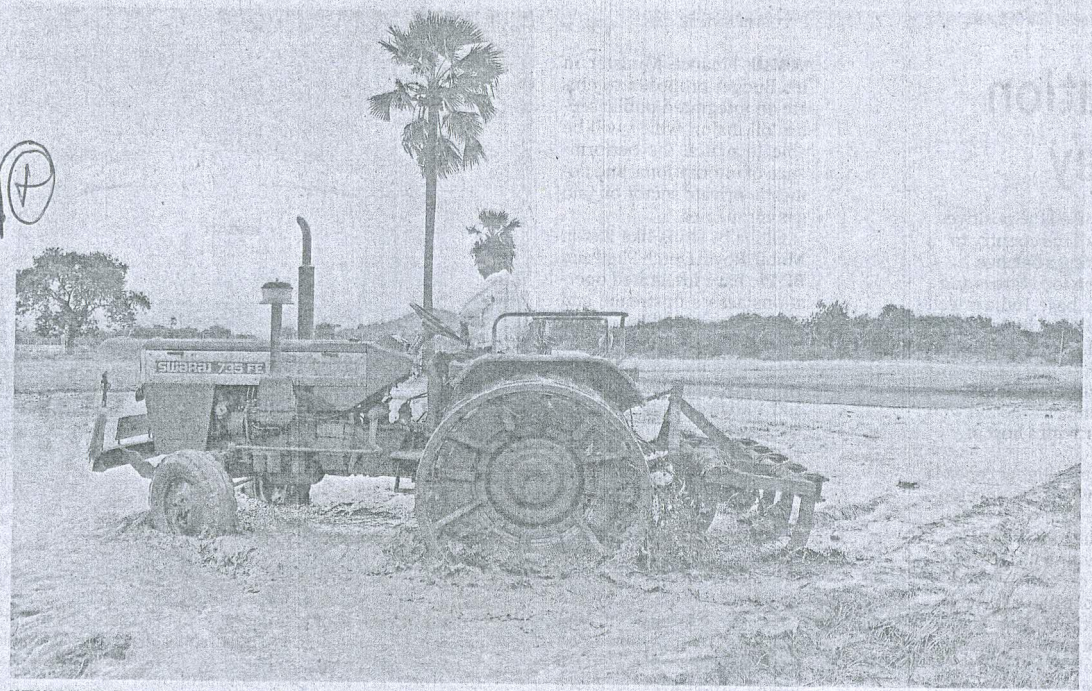

WEAK COVER: Farmer groups say that more than their members, it is insurance companies that have benefited from the Fasal Bima Yojana scheme. —FILE PHOTO: THAKUR AJAY PAL SINGH

AGRICULTURE

'High credit, crop insurance scheme positive measures'

MUMBAI: The Centre has taken up several measures to revive country's agriculture economy in the Union Budget 2017—18 such as higher agricultural credit, higher allocation for irrigation projects, crop insurance scheme, agricultural experts said.

"Several measures to revive the agricultural economy such as higher agricultural credit, higher allocation for irrigation projects, crop insurance scheme and, MGNREGA scheme, besides expansion in coverage of eNAM, will help fertilisers companies in the medium term through higher demand," rating agency ICRA's Group Head, Corporate Sector ratings K Ravichandran said.

Rajiv Tevtiya, Managing Partner & CEO, RML AgTech said the Finance Minister has presented a great budget for agriculture with emphasis on all critical areas for an overall and coherent growth of the farmers. With the allocation of ₹10,000 crore to BharatNet Project and the set target of reaching nearly 1.5 lakh gram panchayats with high—speed Internet will lay the foundation of digital revolution in agriculture. — PTI

The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz
and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

News item/letter/article/editorial published on February 2.2.2017 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	A a j (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)&...

एनजीटी के आदेश को ताक पर रखकर छलनी कर रहे नर्मदा

RP 2-2-17

पत्रिका लाइव रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

पानी में भी खनन... सीहोर में नर्मदा तट पर मौजूद जोशीपुर गांव में ऐसे हो रहा अवैध रेत खनन।

बुदनी/सीहोर एनजीटी ने नदियों में खनन को लेकर साफ आदेश दिया है कि बहती नदी से किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा। पर प्रदेश का बेखौफ रेत माफिया इन आदेशों का धता बताते हुए बीच धार में से रात-दिन खनन करने में जुटे हैं। पत्रिका ने जब मंगलवार को पड़ताल की तो स्थिति होश उड़ा देने वाली निकली। बुदनी से 7 किमी दूर नर्मदा तट पर स्थित गांव जोशीपुर रेत के अवैध कारोबार का गढ़ बना हुआ है।

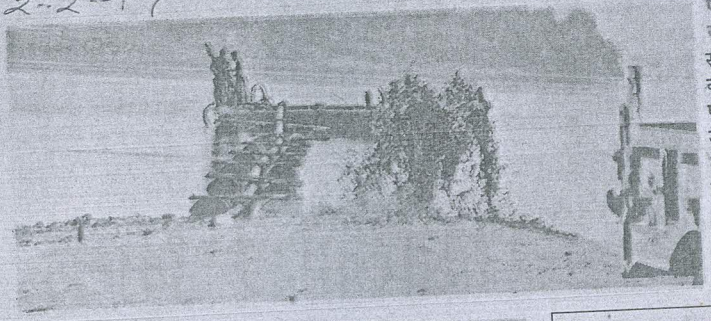

बीच धार में नाव खड़ी कर रेत का खनन

यहां जलपरी की मदद से नर्मदा नदी का सीना चीर कर माफिया रेत निकाल रहे हैं। यहां एक दिन में 40 से 60 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत निकाली जा रही है। मंगलवार करीब एक बजे जब पत्रिका टीम नर्मदा नदी के जोशीपुर घाट पहुंची तो यहां तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े थे। बीच नदी में नाव पर जलपरी से रेत निकालकर उसे नर्मदा के घाट पर फेंक रही थी। जबकि उसका पानी छनकर वापस नदी में आ रहा था। यहां काम कर रहे मजदूर ने बताया कि यह रेत सूखने के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली से जोशीपुर गांव पहुंचाई जाएगी। गांववालों ने भी अवैध रेत कारोबार को अपनी रोजीरोटी बना लिया है। 60 से 70 फीसदी लोग रेत के अवैध करोबार से जुड़े हुए हैं। गांव में हर दूसरे-तीसरे घर के सामने बड़े-बड़े रेत के ढेर लगे हैं।

रतलाम: मलेनी नदी के पेटे से निकाल रहे रेत

जावरा के दूधाखेड़ी गांव के समीप मलेनी नदी क्षेत्र पर मंगलवार को पहुंचकर देखा तो वहां तीन ट्रैक्टर रेत परिवहन की तैयारी में नजर आए। ये ट्रैक्टर रेत लेकर कुछ दूरी पर जावरा आलोट मार्ग पर पहुंचते है, वहां सड़क किनारे रेत उड़ेलकर, यहीं से बेचा जाता है। यहां उड़ेली हुई रेत नजर आई। नदी क्षेत्र में रेत खोदने से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है, गड्ढों के पास बार-बार ट्रैक्टर आने-जाने से कच्चा मार्ग बन गया है। रेत परिवहन में लिप्त लोगों को किसी का डर नहीं है। इन खनन कारोबारियों का नेटवर्क इतना इतना फैला हुआ है कि यदि कोई कार्रवाई करने आए तो उनके पहुंचने से पहले ही इन्हें सूचना मिल जाती है।

भिंड : बंदूक के साए में अवैध खनन

भिण्ड. भिण्ड और आस-पास के क्षेत्र में रसूखदार बंदूक के साए में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। मंगलवार को पत्रिका टीम गोरमी क्षेत्र स्थित सिंध नदी के किनारे पहुंची तो दर्जनभर हथियारों से लैस माफिया की मौजूदगी में थीडी और पोकलेन मशीन से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे दिनभर रेत का अवैध परिवहन होता है, लेकिन रसूख के आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वीकृत खदानों के नाम पर सिंध नदी के अस्वीकृत क्षेत्र से खनन हो रहा है। लहार के मटियावली रेत खदान पर भी यही आलम है। पर्दे के पीछे से रसूखदार अवैध खनन में लिप्त हैं। इध इस मामले में भिंड जिले के जिला खनिज अधिकारी राजेंद्र भदकारिया का कहना है कि एक वर्ष में जिले की तीन दर्जन से अधिक रेत खदानों पर दो दर्जन बार छापा मारा गया लेकिन एक भी माफिया नामजद नहीं हुआ। अधिकारी कार्रवाई के दौरान डंपर, ट्रैक्टर, थीडी, पोकलेन मशीन पकड़ लेते हैं, लेकिन खनन करने वाले जुर्माना देकर इनको छुड़ाकर ले जाते हैं। कागज में किसी रसूखदार का नाम नहीं आने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो कानूनी प्रावधान हैं वैसे कार्रवाई करते हैं।

इधर, जबलपुर में घाट गुंडों के हवाले

जबलपुर. नर्मदा और हिरन के घाटों पर जबलपुर ब्लॉक से लेकर शहपुरा व कटंगी तक 12 से ज्यादा स्थानों पर रेत का अवैध उत्खनन होता नजर आया। एक घाट पर तो रेत माफिया के गुर्गों ने 'पत्रिका' टीम को घेर लिया। रिपोर्टर और फोटो जर्नलिस्ट से बदसलूकी की। वे धमकाते रहे। कहा कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसे प्रशासन या पुलिस कोई नहीं रोक सकता। जो भी इस काम को रोकने की कोशिश करेगा, वह दुनिया में नहीं रहेगा। 'पत्रिका' ने इस घटना की जानकारी कलेक्टर महेशचंद्र चौधरी व एसपी महेन्द्र सिंह सिकरवार को दे दी है।

अधिक जानकारी के लिए लॉगऑन करें...
patrika.com/state